

10-02-2023 Regarding increasing Emoluments for Physical Education in Leh and Kargil and Regularising them with along with scrapping of Rehbar-e-Khel (REK) Policy. SPECIAL MENTION (ZERO HOUR) Namgyal, Shri Jamyang Tsering Salary

Title: Regarding increasing emoluments for physical education in Leh and Kargil and regularising them with along with scrapping of Rehbar-e-Khel (REK) Policy.

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): सभापति जी, आपने शून्य काल में मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सर, अस्टर्टवाइल जम्मू-कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वर्ष 2005-06 एक कैबिनेट डिस्मिशन के माध्यम से स्टेट में एक पॉलिसी लाई गई, जिसके माध्यम से जितने भी सरकारी मिडिल स्कूल, हायर स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल आदि सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स, गेम्स और फिजिकल एजुकेशन को कम्पलसरी किया गया और जिसको ठीक ढंग से चलाने के लिए हर स्कूल में कम से कम एक-एक फिजिकल एजुकेशन टीचर एप्वाइंट करने का निर्णय लिया गया था। पूरे जम्मू-कश्मीर, इनक्लूडिंग लद्दाख में यह एक्सरसाइज हुई थी। ऐसी 30 हजार पोस्ट्स क्रिएट की गई थीं। उनमें सभी युवा, जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएट किया हो और उसके ऊपर एमपीएड किया हो या बीपीएड किया हो या उससे अधिक क्वालीफिकेशन रखते हों, उन लोगों को एप्वाइंट किया गया। यह भी निर्णय किया गया था कि जिस ज़ोन में स्कूल है, उसी ज़ोन से कैंडीडेट्स को एप्वाइंट करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन कैंडीडेट्स का जो सात साल का टेन्योर है, उसमें वे रेगुलराइज नहीं होंगे। उन सात वर्षों में से पहले के दो वर्षों में उनको प्रतिमाह 3 हजार रुपये ही मिलेंगे, उसके बाद पांच साल उनको केवल 4 हजार रुपये ही मिलेंगे। अब लद्दाख और जम्मू-कश्मीर अलग होने के बाद भी यह व्यवस्था कंटीन्यू चल रही है। आपके माध्यम से, मेरा सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से विशेष निवेदन यह है कि जम्मू-कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेचर है, जब स्टेट गवर्नमेंट बनेगी तो वहां का डिस्मिशन हो जाएगा। लद्दाख में, लेह और कारगिल में ऐसे 98 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, जिनको रहबरे-खेल का नाम दिया गया, जो प्रतिमाह 3 हजार या 4 हजार रुपये में इतने दुर्गम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनका मानदेय 3 हजार रुपये और 4 हजार रुपये से बढ़ाकर कम से कम 18 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए, जो भारत सरकार के सेवंध पे कमीशन में मिनिमम वेज है। उनको कम से कम 18 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएं।

दूसरा, जितने भी ऐसे लोग हैं, उनके लिए अलग से पोस्ट्स क्रिएट करके, उनको रेगुलराइज किया जाए और लाँग रन के लिए यह रहबरे-खेल की पॉलिसी लद्दाख में खत्म की जाए, स्क्रेप की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।